(iii) *Re.* KAPADIAS' ATTEMPT TO GET CONTROL OVER NATIONAL RAYON CORPORATION, LTD.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, 1968 के अन्तिम महीनों में मैंने कापड़िया के द्वारा किलिक निक्सन गुट की कम्पनियों पर कब्जा करने की जो साजिश की गई थी, उस के सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र उद्योग मंत्री को दिया था पिछली लोक सभा में यह मामला कई बार उठा था । मेरे प्रयासों के चलते अहमदाबाद, सूरत और बम्बई उपनगरों की बिजली कम्पनियों का पूरा इन्तजाम अपने हाथों में लेने की उन की कोशिश असफल हो गई । नेशनल रेयान को हथियाने का उन का प्रयास भी मैंने कामयाब होने नहीं दिया था ।

हम लोगों के आग्रह पर सरकार ने कम्पनी कानून की खंड 408 के तेहत कार्यवाही की और जनता तथा हिस्सेदारों के हित की रक्षा की । अपने आदेश में कम्पनी ला बोर्ड ने कापड़िया के अस्वस्थ तौर तरीके, उनका सन्देहास्पद पूर्व-इतिहास, उन की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति तथा उन के द्वारा किया गया वचनभंग आदि की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की थी ।

अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार ने खंड 408 के अन्दर की गई कार्यवाही को जारी नहीं रखा, सरकारी डायरैक्टरों की मियाद नहीं बढ़ाई तो हिस्सेदारों की 11 मई की वार्षिक सभा में वह कम्पनी कापड़िया के हाथ में चली जायगी और जिस तरह तीन वर्ष पहले उन्होंने कोहिनूर मिल्स का विनाश किया, नेशनल रेयान का भी करने से वे बाज नहीं आयेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल रेयान बहुत महत्व की कम्पनी है । उस की परिसंपत्ति (एसेट्स) 30 करोड़ रुपया है और सालाना बिक्री 29 करोड़ रुपये की है । यह कम्पनी सरकार को पौने छः करोड़ सालाना आबकारी कर (एक्साईज ड्यूटी) तथा ढाई करोड़ रुपये कारपोरेशन टैक्स के रूप में देती है—यानी कुल सवा आठ करोड़ रुपया देती है । चूंकि एक कापड़िया मारुति लिमिटेड का डायरैक्टर है, इसलिये जनता और हिस्सेदारों के मन में सरकारी दृष्टिकोण के बारे में शंका उत्पन्न हुई है । क्या सरकार अविलम्ब इस में कार्यवाही कर इस शुब्हे को दूर करेगी ?

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Only the Member who was allowed could speak. The Minister should make a statement about it sometime later to-day or tomorrow at the earliest.

(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI D. R. CHAVAN): Sir, this matter is before the Company Law Board. I shall make a statement on this tomorrow after collecting the information

---

13.25 hrs.

NORTH-EASTERN HILL UNIVERSITY BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We shall now resume discussion on the North-Eastern Hill University Bill. I have gone through the point raised by Shri Madhu Limaye, Shri Daga and Shri Indrajit Gupta and also your views on it, namely, that you will be coming with some amendments later on for restoring the position of autonomy. You said that in fact the university authorities had been given autonomy under the delegated legislation. So far as Government is concerned this autonomy is all right. But, so far as the universities and this Parliament are concerned, it is very difficult to admit that autonomy. So, the papers should be laid on the Table of the House so far as Statutes are concerned. Whenever any Statute is issued, amended or discontinued, a copy thereof should be laid on the Table of the House. I have seen that so far as Banaras Hindus University, Jawaharlal Nehru University and Aligarh University are concerned, in all these universities, under the Statute, it is said that the Court shall consist of the following. Under that, a list of 28 categories is given so far as the Banaras Hindu University is concerned.

Similarly, in the case of Jawaharlal Nehru University also a list of categories is given. In the case of Aligarh University also, there is a list of 32 categories. But, in this case, it has been mentioned in the Bill that the constitution of the Court and the terms of its members shall be prescribed by the Statutes which may be made by the Executive body. No categories or any other details are given. Similarly, in the case of the Executive Council, the categories are given in the case of Jawaharlal